

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] दिल्ली, नवम्बर 6—नवम्बर 12, 2015, बृहस्पतिवार/कार्तिक 15—कार्तिक 21, 1937 [रा.रा.क्षे.दि.सं.139
No. 18] DELHI, NOVEMBER 6—NOVEMBER 12, 2015, THURSDAY/KARTIKA 15—KARTIKA 21, 1937 [N.C.T.D. No. 139

भाग—IV

PART-IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than

Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 6 नवम्बर, 2015

शक्तियां

सं. 131/गजट/एफ. न्यायिक 1(ए) शक्तियां.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 381/Gaz./F. Judl. 1(a) Powers दिनांक 21 जुलाई, 2003 में आंशिक आशोधन करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशगण पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (रा.रा.क्षे. दिल्ली में यथा प्रवृत्त) की धारा 25 संपठित धारा 21(2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 से वाद/मुकदमें जिनका अधिकारिता मूल्य रु. 3,00,000 (रुपये तीन लाख) से अधिक परन्तु रु. 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़) से कम है जिला न्यायाधीश दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जो या तो स्वयं उन्हें निपटायेंगे अथवा विधि अनुसार उन्हें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में निपटाने हेतु स्थानांतरित करेंगे।

आदेशानुसार,

विनोद गोयल, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 6th November, 2015

POWERS

No. 131/Gaz./F. Judl. 1(a) Powers.—In partial modification of this Court's Notification No. 381/Gaz./F.Judl. 1(a) Powers dated the 21st July, 2003, Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges of the High Court of Delhi in exercise of the powers conferred by Section 25 read with Section 21(2) of the Punjab Courts Act, 1918 (as in force in NCT of Delhi), have been pleased to order that with effect from 26th October 2015, suits/cases of which the jurisdictional value exceeds Rs. 3,00,000 (Rupees three lacs) but does not exceed Rs. 2,00,00,000 (Rupees two crores) shall be presented to the District Judge, Delhi, who may either himself dispose them of or transfer them to the Court of an Additional District Judge for disposal according to law.

By Order ,
VINOD GOEL, Registrar General